Pending claims of Gujarat for investment subsidy

1448. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of claims of Gujarat for Central investment subsidy pending with the Union Government at present;

(b) the reasons for their non-clearance so far;

(c) the time by which these claims are likely to be disbursed; and

(d) the agency through which these claims are disbursed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) The Central Investment Subsidy Scheme was discontinued with effect from 1.10.1988. At present no eligible claim from the Government of Gujarat is pending with the Central Government under the scheme.

(b) to (d) Do not arise.

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का कार्यकरण

1449. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या 1993-94 में इन प्रतिष्ठानों की कार्य-कुशलता और लाभ-अर्जन की स्थिति में कोई सुधार आया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रतिष्ठानों की कार्यकुलता और लाभ-अर्जन की स्थिति मे सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) केवल 31 मार्च, 1993 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार उक्त तारीख तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित 6 उद्यमों के पूंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित थे :

1. फेरो स्क्रैप निगम लि०
2. एम-पी अशोक होटल निगम लि०
3. नेपा लि०
4. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०
5. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०
6. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

(ख) और (ग) 26 फरवरी, 1994 को संसद् में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड -1 के विवरणी पृष्ठ सं० 147 से 180 तक में विगत तीन वर्ष के उद्यमवार वास्तविक उत्पादन का तथा विवरणी पृष्ठ सं० 42 से 50 तक में विगत पांच वर्ष के उद्यमवार निवल लाभ हानि का उल्लेख किया गया है।

(घ) कार्यक्षमता एवं लाभकारिता में सुधार हेतु कार्रवाई उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार की जाती है। बहरहाल, उद्यमों की कार्यक्षमता एवं लाभकारिता में सुधार हेतु सामान्य तौर पर किए जाने वाल उपायों का उल्लेख लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के खण्ड-1 के पृष्ठ सं० 150 में किया गया है।